

# कथा दुर्घटनावश बने प्रधानमंत्री और सत्ता के दो केन्द्रों की

मुशरफ़ अली

एक साल के अन्दर दो किताबें आयीं हैं जो नेहरु परिवार पर केन्द्रित हैं एक संजय बारु द्वारा लिखी किताब 'एक्सीडेन्टल प्राइम मिस्टर' व दूसरी श्री नटवर सिंह द्वारा लिखित, "वन लाईफ़ इज़ नॉट एनफ़"। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार डा० संजय बारु की 2014 के चुनाव के बीच आई किताब 'द एक्सीडेन्टल प्राइमिनिस्टर' यानि दुर्घटनावश बने प्रधानमंत्री ने भाजपा द्वारा सन् 2004 में श्रीमति सोनिया गाँधी पर लगाये गए आरोपों को फिरसे बहस में ला दिया है। श्री संजय बारु की किताब या उनके इस तरह के बयान उस समय क्यों नहीं आए जब वह श्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे या 2008 में मीडिया सलाहकार के पद से हटाये जाने के तुरन्त बाद भी उन्होंने अपने उद्गार क्यों नहीं प्रकट किए और क्यों वह 6 साल तक खामोश रहे इस बात ने उनकी नियत पर सवाल खड़े कर दिये हैं। लोग यह भी कह रहे हैं कि आगामी सरकार भाजपा की बनेगी और उसमें उनको अपनी इस वफ़ादारी के ऐवज़ में कोई काम मिल जाएगा इसका अनुमान लगाकर ही श्री संजय बारु ने भाजपा के पहले से जारी प्रचार के पक्ष में इस किताब को प्रकाशित कराया है।

हालांकि अपनी किताब द्वारा उन्होंने श्रीमति सोनिया गाँधी पर निशाना साधते हुए श्री मनमोहन सिंह को बेचारा व बेबस साबित करने की कोशिश की है लेकिन उनकी इस कोशिश का एक पहलू श्री मनमोहन सिंह द्वारा जनविरोधी आर्थिक सुधार के मोर्चे पर हासिल की गई उपलब्धियों पर पानी फेरना भी है जिससे श्री मनमोहन सिंह बुरी तरह नाराज़ हो उठे हैं। कोई व्यक्ति देश भर में इतनी बदनामी झेलने के बाद भी मुक्तबाज़ार की आर्थिक नीतियों को लागू करने की भरसक कोशिश करे ऐसे में बजाए उसकी तारीफ़ करने के उसे नाकारा कहने की कोशिश की जाए तो उससे उसका नाराज़ होना स्वाभाविक है।

श्री संजय बारु की यह स्थापना कि कांग्रेस में सत्ता के दो केन्द्र बने हुए हैं एक श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मुक्त बाज़ार के हिमायतियों का और दूसरा श्रीमति सोनिया गाँधी के नेतृत्व में नवउदारवादी पूंजीवाद के विरोधियों का, उनकी अपनी मौलिक स्थापना नहीं है। उन्होंने यह बात भाजपा से ज्यों की त्यों लेली है। उनका यह कहना कि संप्रग-2 में सत्ता के यह दो केन्द्र एक केन्द्र यानि श्रीमति सोनिया गाँधी वाले केन्द्र में बदल चुके हैं, सच्चाई से कोसों दूर है। मनमोहन सिंह की बेचारगी या बेबसी का कारण, रिमोट का श्रीमति सोनिया गाँधी के हाथ में होना है यह बात भी नवउदारवादियों का सुनियोजित प्रचार ही है ताकि जनविरोधी आर्थिक सुधार के दुःपरिणामों की ज़िम्मेदारी श्रीमति सोनिया गाँधी पर डाली जा सके। रिमोट श्रीमति सोनिया गाँधी के हाथ में है इस विचार को अपनाने में लोगों में मौजूद साम्प्रदायिक रुझान मदद करता है। श्रीमति सोनिया गाँधी क्योंकि इसाई हैं इसलिए उनकी वफ़ादारी इसाई अमरीका और यूरोप के साथ होगी, साम्प्रदायिक सोच इस अवधारणा को विश्वास में बदल देती है। विवेकवान व्यक्ति के मन में यह सवाल उठ सकता है कि पूर्व सोवियतसंघ, लेटिन अमरीका व यूगोस्लाविया जो इसाई बहुल देश हैं उन्हें बर्बाद करने की कार्यवाही इसाई अमरीका और यूरोप क्यों करते हैं ? लेकिन साम्प्रदायिक मनोस्थिति में क्योंकि विवेक काम नहीं करता इसलिए अन्ना हज़ारे से लेकर स्वामी रामदेव तक यह बात कहते नज़र आते हैं कि रिमोट सोनिया गाँधी के हाथ में है जबकि सच्चाई इसके उलट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर विश्वहिन्दू परिषद और भाजपा तक इसाई अमरीका की नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के न केवल पक्ष में खड़े हैं बल्कि भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के छह साल के शासनकाल में वह उन नीतियों को व्यवहार में तत्परता से उतारते नज़र आते हैं। स्वामी रामदेव के तो मंच से नवउदारवादियों का नारा, "न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन" जो अब नरेन्द्र मोदी लगा रहे हैं कुछ इस तरह से लगाया जाता रहा है कि " जहाँ की सरकार व्यापारी है वहाँ की जनता भिखारी है। " हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद का नारा देने वाले संघ का इसाई अमरीका के साथ खड़ा होना इस हकीकत को उजागर करता है कि आर्थिक नीतियां धार्मिक पक्षधरता के स्थान पर वर्गीय पक्षधरता से संचालित होती है।

अभी-अभी एक दूसरी किताब श्री नटवर सिंह की, "वन लाईफ़ इज़ नॉट एनफ़" यानि एक जिन्दगी काफ़ी नहीं, आई है जिसमें कहा गया है कि यू.पी.ए. एक के समय सोनिया गाँधी को प्रधानमंत्री बनने से राहुल गाँधी ने रोका था। उन्हें इस बात का डर था कि जिस ताकत ने उनकी दादी श्रीमति इन्द्रा गाँधी और पिता श्री राजीव गाँधी की निर्मम हत्या कराई है वह ही उनकी माँ श्रीमति सोनिया गाँधी की भी हत्या करा सकती है इसलिए उन्होंने अपनी माँ की जिन्दगी बचाने के लिए उनपर प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए दबाव डाला। इस रहस्योद्घाटन पर जानबूझकर चर्चा को श्रीमति सोनिया गाँधी की छवि को धूमिल करने की ओर मोड़ दिया गया। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद छोड़ना कोई त्याग की बात नहीं थी बल्कि राहुल गाँधी के दबाव के कारण उन्होंने ऐसा किया था।

रिमोट श्रीमति सोनिया गाँधी के हाथ में है इस प्रचार की शुरुआत सन् 2004 में बनी कांग्रेसनीत संग्रग-1 सरकार के समय से ही हो चुकी थी। वाममोर्चे का समर्थन क्योंकि 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' को लागू किए जाने की शर्तों पर आधारित था इसलिए उस कार्यक्रम को लागू कराने के लिए ही 'राष्ट्रीय सलाहकार परिषद' का गठन श्रीमति सोनिया गाँधी की चेयरपर्सनशिप में किया गया। यही वह दूसरा सत्ता का केन्द्र बना जो नवउदारवादी पूंजीवाद यानि मुक्त बाजार के समर्थकों की आँखों में चुभने लगा। यह केन्द्र आर्थिक सुधार को लागू करने में बाधा बनेगा इसका अनुमान इसके विरोधियों को लग चुका था इसलिए उन्होंने इस केन्द्र का विरोध इसके जन्म के बाद से ही करना शुरु कर दिया। जो बात श्री संजय बारु ने अपनी किताब में अब लिखी है वह जुलाई 2004 में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद श्री थावरचन्द गहलोत ने पी.टी.आई. से इन्दौर में कही थी, "संविधान में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाने का कोई प्रावधान नहीं है और श्रीमति सोनिया गाँधी का उसका चेयरपर्सन होना गैर संविधानिक है।" उन्होंने आगे कहा कि यह पता चला है कि कांग्रेस के मंत्री सभी महत्वपूर्ण फ़ाईलों को श्रीमति सोनिया गाँधी को दिखा रहे हैं और वह सुपर प्रधानमंत्री की तरह काम कर रही हैं।" फ़ाईलें दिखाने की यही बात श्री संजय बारु ने अपनी किताब में ज्यों की त्यों लिख दी है।

सांसद किसी अन्य लाभ के पद पर जहाँ उसे मानदेय या वेतन मिलता हो काम नहीं कर सकता यह मुद्दा समाजवादी पार्टी के कोटे से बनी राज्य सभा सांसद श्रीमति जयाबच्चन के फिल्म सेन्सर बोर्ड के सदस्य बनने पर उठा था इसी को आधार बना कर श्रीमति सोनिया गाँधी पर विपक्ष ने दबाव डाला और उन्होंने 2006 में 'राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के चेयरपर्सन पद से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद जब वर्ष 2009 में संग्रग-2 की सरकार बनी तब दोबारा 29 मार्च 2010 को श्रीमति सोनिया गाँधी की चेयरपर्सनशिप में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन का आदेश निकाला गया उसके अगले दिन ही भाजपा ने उसपर हमला बोल दिया। 30 मार्च 2010 को एजेन्सियों के हवाले से छपी खबरों के अनुसार भाजपा के प्रवक्ता राजीव प्रताप रुड़ी ने कहा, "श्रीमति सोनिया गाँधी की बतौर चेयरपर्सन नियुक्ति एक छद्म संविधानिक सत्ता के केन्द्र का उभरना है। हमारे पास पहले से ही एक अस्थिर प्रधानमंत्री है जो मँहगाई, आतंक और विफल विदेश नीति की चुनौतियों से चकराया हुआ है उसपर श्रीमति गाँधी की बतौर सुपरवाइज़र की स्थिति ने सरकार के मुखिया होने के प्रधानमंत्री के पद को ही निरर्थक कर दिया है। यह लोकतंत्र के लिये खतरनाक है कि देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे संविधान ने प्रधानमंत्री का पद सौंपा है उसके आत्मविश्वास को कमतर किया जाए। भाजपा के ही दूसरे प्रवक्ता प्रकाश जावेडकर ने कहा, "श्रीमति गाँधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के चेयरपर्सन पद पर नियुक्ति ने रिमूट कन्ट्रोल होने के बहाने को भी समाप्त कर दिया है जो काम पहले रिमोट कन्ट्रोल द्वारा होता था अब सीधे-सीधे होने लगा है।"

श्री संजय बारु का यह कहना कि संग्रग-2 में सत्ता का केन्द्र एक ही रह गया था हकीकत के एक दम खिलाफ़ है क्योंकि इस दौर में ही मनमोहन सिंह ने अमरीकी अर्थशास्त्रियों के रुके हुये एजेन्डे को लागू किया। संग्रग-1 में तो वामपंथियों ने उस एजेन्डे को ठन्डे बस्ते में डलवा दिया था और दूसरी पीढ़ी के सुधार, जिनके तहत सरकारी बैंक व बीमे का निजीकरण व बचे हुए सरकारी कारखानों को बेचा जाना और रिटेल मल्टी ब्रॉड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाना शामिल था, रुक गये थे। उन्होंने विनिवेश मंत्रालय जो खुद को देशभक्त व स्वदेशी कहलाने वाले संघी नेताओं ने आधुनिक भारत के मन्दिर कहलाने वाले कारखानों को बेचने के मकसद से खोला था उसे ही बंद करवा दिया था। इन तथाकथित सुधारों को न कर पाने की बेबसी को श्री मनमोहन सिंह ने 2009 में वामपंथियों के बिना समर्थन के बनी संग्रग-2 की सरकार के गठन के अवसर पर संसद में दिए भाषण में कुछ इस तरह से प्रकट किया, "वामपंथियों ने इन बीते चार सालों में मुझे बंधुआ मजदूर बनाकर रखा।"

मनमोहन सिंह ने अपने इस दूसरे कार्यकाल में सत्ता के दूसरे केन्द्र यानि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सुझावों को मानने से लगातार इंकार किया और उसके फैसलों को जितना टाला जा सकता था टाला। संग्रग-1 व 2 के कार्यकाल में बुनियादी अन्तर यह था कि पहले को आज्ञापत्र, स्पष्टरूप में न्यूनतम साझा कार्यक्रम से मिला था और उसे लागू किए जाने का दबाव वामपंथियों की ओर से था जबकि दूसरे कार्यकाल में न्यूनतम साझा कार्यक्रम मौजूद ही नहीं था जिसे लागू किए जाने का वामपंथियों का दबाव होता। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद थी भी तो उसे आज्ञापत्र, दिनांक 4 जून 2009 को संसद में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण से मिला था। जो बाते अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कही थी उन्हें लागू करने के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी 'रासप' पर थी। संग्रग के दूसरे कार्यकाल में सोनिया गाँधी के नेतृत्व में 'रासप' के नाम पर बना सत्ता का यह दूसरा केन्द्र इतना कमजोर हो चुका था कि उसे भोजन का अधिकार मंजूर कराने में तीन साल लग गए जबकि पहले कार्यकाल में 'नरेगा' को लागू कराने में न तो इतना समय लगा न ही इतनी मशक्कत करनी पड़ी। इस केन्द्र के कमजोर होने की दूसरी मिसाल पेट्रोल का डी-कन्ट्रोल किया जाना और रसोई गैस के सिलिंडरों की संख्या को घटाया जाना और रिटेल में मल्टी ब्राण्ड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 51 प्रतिशत किया जाना है। जबकि श्री संजय बारु सत्ता के इस दूसरे केन्द्र को ही

सर्वाक्तिमान बता रहे हैं।

मीडिया में चर्चा से यह बात एकदम गायब है कि सत्ता के यह दोनो केन्द्र काम क्या करते रहे हैं। कौन सा आम जनता के हित में और कौन सा विरोध में फैसले लेता रहा है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि सत्ता का पहला केन्द्र जो श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में काम कर रहा है वह सड़ रहे अनाज को गरीबों को बाँटने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को मानने से साफ़ इंकार कर रहा था जबकि दूसरा केन्द्र जो विदेशी मूल की महिला श्रीमति सोनिया गाँधी के नेतृत्व में भोजन के अधिकार को मंजूर कराने में ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। जहाँ दूसरा केन्द्र मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी लागू कराने की कोशिश में लगा हुआ था वहीं पहला केन्द्र कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा न्यूनतम मजदूरी लागू किए जाने के पक्ष में दिए गए फैसले के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। मनमोहन सिंह सरकार के इस फैसले के विरोध में ही सुश्री अरुणा राय ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया था। यहाँ यह बात गौर करने की है कि गरीब जनता के खिलाफ़ खड़े पहले केन्द्र के पक्ष में स्वयं को देशभक्त बताने वाली भाजपा खड़ी है जबकि दूसरे केन्द्र द्वारा जनता के हित में किए जा रहे फैसलों के पक्ष में केवल और केवल वामपंथी खड़े हैं। यूं तो कहा जाता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है लेकिन प्रचार की इस आँधी में साम्प्रदायिकता से संक्रमित लोग उस केन्द्र के पक्ष में खड़े हो जाते हैं जो उनके ही खिलाफ़ है। जब दुनिया दो ध्रुवीय थी तब ज़्यादा सुरक्षित थी लेकिन एक ध्रुवीय होते ही जो नतीजे सामने आए हैं वह सबके सामने हैं। सत्ता के चाहे एक, दो या अनेक केन्द्र हों बात इससे तय नहीं होती है असली बात इससे तय होती है कि सत्ता के यह केन्द्र किसके पक्ष में काम कर रहे हैं। संजय बारू सत्ता के जिन दो केन्द्रों की बात कर रहे हैं, ठोस सबूतों की रोशनी में आईये इनकी पड़ताल करते हैं।

इन दोनो केन्द्रों के कामों की पड़ताल कोई मुश्किल काम नहीं है। यह काम बिना किसी अर्थशास्त्री या विशेषज्ञ के, सामान्य लोग भी कर सकते हैं। श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कार्यरत सत्ता केन्द्र ने जो अपने कार्यकाल में काम किये हैं उससे आम जनता अच्छी तरह वाकिफ़ है लेकिन श्रीमति सोनिया गाँधी के नेतृत्व में काम कर रहे सत्ता के इस दूसरे केन्द्र यानि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कामों के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इस दूसरे केन्द्र के कामों को जानने के लिए आपको इस परिषद की वेबसाइट पर जाना होगा। नीचे लेख के अन्त में हम दोनो केन्द्रों के प्रमुख कामों को आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप तय कर सकें कि कौनसा केन्द्र तबतक बना रहना चाहिए जबतक उससे बेहतर न बन जाए और कौनसा नहीं बनना चाहिए।

श्री संजय बारू ने अभी हाल ही में एक चैनल को दिये साक्षात्कार में बताया है कि श्रीमति सोनिया गाँधी द्वारा श्री मनमोहन सिंह को खुलकर काम नहीं करने दिया गया जिस का परिणाम कांग्रेस को 2014 के चुनाव में उठाना पड़ रहा है। यह उनका इतना बड़ा झूठ है जिसपर केवल हँसा ही जा सकता है क्योंकि कांग्रेस की इस दुर्गति का एकमात्र कारण केवल श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रहे केन्द्र का आम जनता के खिलाफ़ फैसले लागू करना रहा है। अगर मनमोहन सिंह तीन साल पहले ही भोजन का अधिकार कानून अम्ल में ले आते, गैस के सिलिंडर कम न करते, पेट्रोल, और चीनी को डी कंट्रोल नहीं करते, डीजल की कीमत धीरे-धीरे नहीं बढ़ाते, जिन्सों की सट्टेबाज़ी न कराते, बाज़ार में हस्तक्षेप करके मंहगाई को रोकते तो 2014 के चुनाव का रिज़ल्ट दूसरा ही होता। अगर यू.पी.ए.-1 के शासनकाल में 'मनरेगा' लागू नहीं किया जाता तो 2009 के चुनाव में ही कांग्रेस बुरी तरह हार जाती और मनमोहन सिंह को अपना दूसरा कार्यकाल नसीब नहीं होता। 2009 में कांग्रेस के दोबारा सत्ता में लौटने का कारण ही सोनिया गाँधी के नेतृत्व में कार्यरत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कुछ हिस्सों का मनमोहन सिंह के केन्द्र के विरोध के बावजूद लागू किया जाना है। संजय बारू जिस निरंकुश सत्ता के एक केन्द्र के पक्ष में किताब लाए हैं वह उनकी संवेदनहीन पूंजीवादी पक्षधरता को बताता है। वह और मीडिया जनता के खिलाफ़ कार्यरत श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कार्यरत इस केन्द्र के जनविरोधी कारनामों को चर्चा से बाहर रखकर उसे बेचारा साबित करने में लगे हैं जबकि श्रीमति सोनिया गाँधी के नेतृत्व में कार्यरत केन्द्र के जनपक्षीय कामों को छिपाकर उसे खलनायक बताया जा रहा है। यह सही है कि श्रीमति सोनिया गाँधी के नेतृत्व में कार्यरत 'राष्ट्रीय सलाहकार परिषद' नामक केन्द्र कोई समाजवादी नीतियां लागू नहीं कर रहा है हाँ इतना जरूर है कि वह आम जनता के प्रति श्री मनमोहन सिंह के केन्द्र की तरह संवेदनहीन नहीं है और लोगों के कुछ आँसू पोंछने की कोशिश जरूर करता है।

आम जनता के खिलाफ़ खड़ा कोई भी केन्द्र चाहे वह मनमोहन-मौन्टेक सिंह के नेतृत्व में हो या नरेन्द्र मोदी के अगर साजिश करके कुछ समय के लिए आ भी जाएगा तो यह तय है कि उसका जीवन स्थाई नहीं होगा। ऐसे केन्द्र को जनता कुछ ही समय बाद कूड़े के ढेर पर फेंक देती है ऐसा हमें इतिहास सिखाता है। नीचे दिए दोनों केन्द्र के कामों से आप खुद फैसला कर लेंगे कि श्री संजय बारू किसको मजबूत देखना चाहते हैं और किसको

कमज़ोर। यह रिपोर्ट उनकी पूंजीवादी पक्षधरता को भी बेनकाब करती है।

श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बने सत्ता केन्द्र के कार्य

श्रीमति सोनिया गाँधी के नेतृत्व में बने सत्ता केन्द्र के कार्य

1. टू-जी स्पेक्ट्रम आवंटन में जनता की सम्पत्ति को 1लाख 76 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया।
2. कोल-ब्लॉक आवंटन से 2 लाख करोड़ रुपए की जनसम्पत्ति का नुकसान।
3. इसरो व देवास मल्टीमीडिया के बीच एस बैंड स्पेक्ट्रम घोटाले से 2 लाख करोड़ रुपए का देश को नुकसान।
4. निजी बिजली कम्पनियों को हर साल 2करोड़ टन विदेशी कोयला आधी कीमत पर 20 साल तक मंगाने की मंजूरी इससे देश को 60 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान।
5. गोदामों में खराब हो रहे अनाज को गरीबों में बाँटने के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए सुझाव को खारिज करना।
6. कॉमनवैल्थ खेल घोटाला।
7. रसोई गैस के सब्सिडी वाले सिलिंडरों की संख्या कम करना पेट्रोल और चीनी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके उनकी कीमतों को बाज़ार के हवाले करना और डीज़ल को धीरे-धीरे डी-कंट्रोल करना।
8. महात्मा गाँधी ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना का सालाना बजट कम करना।
9. भोजन के अधिकार बिल को तीन साल तक लटकाये रखना।
10. टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले से हुये नुकसान की तुलना राशन के अनाज पर दी जाने वाली सब्सिडी से करना।
11. वित्तीय क्षेत्र के सुधार के नाम पर बैंको के निजीकरण की योजना बनाना और रिज़र्व बैंक की ताकत को कम करने के लिए फ़ाईनेन्शियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफ़ॉर्म कमीशन का गठन करना।
12. गन्ना किसानों के पैसे का भुगतान न करने वाले चीनी मिल मालिकों पर कार्यवाही करने के स्थान पर 6600 करोड़ रुपए बिना ब्याज़ के पांच साल के लिए उन्हें दिया जाना।
13. योजना मंत्रालय में जनता के खिलाफ़ व पूंजीपतियों के पक्ष में योजनायें बनाकर उसका उद्देश्य ही बदल देना।
14. दो लाख 90 हज़ार किसानों द्वारा आत्महत्या किया जाना और 77 प्रतिशत जनता की आमदनी 20 रुपये रोज़ पर पंहुचा देना।
15. निजीकरण के लिये पी.पी.पी. जैसी योजनायें लागू करना।

1. हाथ से मल उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए सिफ़ारिश।
2. कार्यस्थल पर यौनउत्पीड़न से मुक्ति दिलाने वाले बिल 2010 पर सुझाव।
3. लक्षित समुदायों के खिलाफ़ साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने वाले बिल को बनाना।
4. ठेला-पटरी वालों की जीविका व सामाजिक सुरक्षा पर सुझाव।
5. मनरेगा द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों के प्रमुख हिस्सों के सुरक्षा प्रबंधन पर सुझाव।
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकार बिल 2011 बनाना।
7. 14 वर्ष तक के बाल मज़दूरों के विकास पर सुझाव।
8. अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना पर सुझाव।
9. राजीव गाँधी आवास योजना पर सुझाव।
10. असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की सामाजिक सुरक्षा पर सुझाव।
11. शहरी बेघर लोगों के आश्रय व अन्य सुविधाओं पर सुझाव।
12. बच्चों के जन्म पर बरते जाने वाले लिंगभेद की समाप्ती पर सुझाव।
13. उत्तर-पूर्व क्षेत्र खेल विकास पर सिफ़ारिश।
14. शिक्षा के अधिकार को मज़बूत करने पर सुझाव।
15. कमज़ोर अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास पर सुझाव।
16. गरीबी रेखा से नीचे की सूची में और लोगों को शामिल करना।
17. छोटी जातों के किसानों को बाज़ार से जोड़कर आय बढ़ाने की सिफ़ारिश।
18. प्रस्तावित विकलांग अधिकार कानून पर सुझाव।
19. चाय बाग़ान मज़दूरों के कल्याण पर सुझाव।
20. यूनीवर्सल हैल्थ कवरेज पर सुझाव।
21. ऐग्रोफोरेस्ट्री पर सुझाव।
22. फ़्लेगशिप योजनाओं के लिये धनापूर्ति करने के लिये सुझाव।
23. सामाजिक क्षेत्र में कौशल विकास पर सुझाव।
24. सहकारिता विकास पर सुझाव।